PCS मंत्र

पीसीएस/यूपीएससी परीक्षा-उन्मुख समसामयिकी

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता: किसानों के हित सर्वोपरि, संवेदनशील क्षेत्र सुरक्षित — गोयल

समाचार-संदर्भ: 29 अक्टूबर 2026 (पीयूष गोयल के बयान)

प्रकाशन: 1 नवंबर 2026

मुख्य परीक्षा: GS-III अर्थव्यवस्था — द्विपक्षीय व्यापार, टैरिफ, कृषि-संवेदनशीलता, ऊर्जा-आयात।

प्रिलिम्स: भारत-अमेरिका व्यापार-वार्ता, तेल-टैरिफ प्रकरण, RCEP निर्णय-तर्क।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

खबरों में क्यों

29 अक्टूबर 2026 को इंस्टीट्यूट फॉर स्टडीज इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट (ISID) के एक सम्मेलन में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ बने द्विपक्षीय व्यापार-समझौते में भारत के संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा हुई है: "भारत के किसानों का एक भी संवेदनशील हित छेड़ा नहीं गया है... विवरण सार्वजनिक होते ही भारत का व्यक्ति खुशी मनाएगा।" उन्होंने कहा कि समझौते के बाद भारत "बहुत मजबूत तुलनात्मक लाभ (comparative advantage)" की स्थिति में होगा। कुछ दिन पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा था कि दोनों देश समझौते के "अविश्वसनीय रूप से करीब" हैं और "99 प्रतिशत काम" पूरा हो चुका है।

समझौते की पृष्ठभूमि: तेल-टैरिफ की गाँठ

PCSMANTRA.COM

इसी माह अमेरिका ने लिंडसे ओ. ग्राहम द्वारा प्रस्तावित Sanctioning Russia and Iran Act, 2026 को रोक दिया — यह विधेयक रूसी तेल खरीदने वाले देशों (भारत और चीन जैसे) पर 100 प्रतिशत तक शुल्क लगाने की अमेरिकी राष्ट्रपति को शक्ति देता है। रूबियो के अनुसार शुल्क-विराम के फैसले में भारत के साथ व्यापार-समझौते को ध्यान में रखा गया। रिपोर्टों के अनुसार तेल-संबंधी शुल्क ही दोनों देशों के बीच मुख्य मतभेद था; अन्य शुल्क-मुद्दों पर अभिसरण बन चुका है। धारा 301 (Section 301) जांचों के बाद भारत जबरन श्रम से बने उत्पादों का आयात पहले ही रोक चुका है, और अधिक्षमता

(overcapacity) वाली जांच पर भारत और अन्य G20 देशों ने कुछ क्षेत्रों — ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, रसायन, बुनियादी सेमीकंडक्टर और सौर पैनल — में संरचनात्मक अधिक्षमता के विरुद्ध कार्रवाई का संयुक्त बयान जारी किया।

गोयल के प्रमुख तर्क

पूरक-लाभ वाली साझेदारी: भारत उन्हीं देशों से समझौता कर रहा है जिनसे पूरक लाभ (complementary advantage) मिलता है; भारत के व्यापार-समझौते 38 विकसित और समृद्ध देशों को कवर करते हैं — भारत उन्हें उनकी ज़रूरत का निर्यात करता है और अपने विकास के लिए आयात करता है।

2014 से पहले की तुलना: पहले के सभी समझौते मिलकर केवल $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्थाओं से थे और प्रतिस्पर्धी प्रकृति के; "असंतुलित समझौते दूर तक नहीं ले जाते।"

RCEP से बाहर रहना सही: गोयल ने 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक में RCEP वार्ता से हटने को भारतीय विनिर्माण के लिए निर्णायक बताया — "वह भारतीय विनिर्माण के लिए मौत की घंटी होती... हम भारत में चीनी सामान बेचने वाले विक्रेताओं का देश बन जाते।" (भारत ने 2019 में कहा था कि RCEP परिणाम "न तो निष्पक्ष है, न संतुलित"; शेष 15 देश — आसियान के 10 तथा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड — आगे बढ़े।)

परीक्षा दृष्टिकोण

व्यापार-वार्ता में "संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा" और "तुलनात्मक लाभ" दो प्रतिस्पर्धी सिद्धांत हैं: पहला कृषि-डेयरी जैसे क्षेत्रों को उदारीकरण से बाहर रखने की माँग करता है, दूसरा शुल्क-विराम से निर्यात-पहुँच बढ़ाता है। साथ ही, शुल्क-विराम और प्रतिबंध-विराम (ग्राहम विधेयक) जैसे भू-राजनीतिक घटक अब व्यापार-वार्ता के अभिन्न हिस्सा हैं — व्यापार-नीति और विदेश-नीति का यह अभिसरण परीक्षा का प्रमुख विषय है।

प्रिलिम्स-बिंदु: RCEP — 15 देश (आसियान 10 + चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड); भारत 4 नवंबर 2019 को वार्ता से हटा; ग्राहम विधेयक — 100 प्रतिशत तक शुल्क; ISID — औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान; भारत के व्यापार-समझौते — 38 विकसित देश (मंत्री के अनुसार)।

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न. "भारत की नई व्यापार-नीति 'पूरक लाभ' के सिद्धांत पर आधारित है, जबकि 'संवेदनशील हितों की रक्षा' उसकी सीमा रेखा है।" भारत-अमेरिका व्यापार-समझौते की हालिया प्रगति के संदर्भ में टिप्पणी कीजिए। (उत्तर 250 शब्दों में लिखिए। 15 अंक)

भूमिका में

ISID सम्मेलन (29 अक्टूबर 2026) में मंत्री के कथन और रूबियो की "99 प्रतिशत" टिप्पणी से संदर्भ दें।

PCSMANTRA.COM

मुख्य भाग में

पूरक-लाभ: 38 विकसित देशों से समझौते; निर्यात-पहुँच और विकास-आयात का द्वैध लाभ; RCEP-निर्णय (2019) को संरक्षण और आत्मनिर्भरता के उदाहरण के रूप में परखें। सीमा रेखा: किसानों के संवेदनशील हित; धारा 301 अभिसरण (जबरन श्रम, अधिक्षमता)। भू-राजनीतिक घटक: ग्राहम विधेयक का विराम और रूसी तेल — व्यापार-वार्ता पर विदेश-नीति का प्रभाव।

निष्कर्ष में

समझौते का परीक्षण विवरण सार्वजनिक होने पर होगा; तब तक "संतुलन" का दावा नीति-आशय के रूप में ही मूल्यांकन योग्य

है।

प्रिलिम्स परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न 1. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: भारत 4 नवंबर 2019 को RCEP वार्ता से हट गया था।
कथन-II: RCEP के सदस्यों में आसियान के दस देशों के अलावा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड शामिल हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं

(b) कथन-I सही है, किंतु कथन-II सही नहीं है

(c) कथन-I सही नहीं है, किंतु कथन-II सही है

(d) कथन-I और कथन-II दोनों सही नहीं हैं

उत्तर और व्याख्या

उत्तर: (a) कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं। भारत ने 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक में RCEP वार्ता से हटने का निर्णय लिया, यह कहते हुए कि परिणाम "निष्पक्ष और संतुलित" नहीं है (कथन-I सही)। शेष 15 देश — आसियान के 10 तथा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड — समझौते के साथ आगे बढ़े (कथन-II सही)।

प्रश्न 2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. अमेरिकी विदेश मंत्री ने भारत-अमेरिका व्यापार-समझौते का "99 प्रतिशत काम" पूरा होना स्वीकार किया है।
2. ग्राहम विधेयक, 2026 रूसी तेल के क्रेता देशों पर 200 प्रतिशत तक शुल्क की शक्ति देता है।
3. वाणिज्य मंत्री ने कहा कि समझौते में किसानों का कोई संवेदनशील हित छेड़ा नहीं गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 1 और 3

(c) केवल 2 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर और व्याख्या

PCSMANTRA.COM

उत्तर: (b) केवल 1 और 3। मार्को रूबियो ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि समझौते का "99 प्रतिशत काम" हो चुका है (कथन 1 सही)। ग्राहम विधेयक 100 प्रतिशत तक — न कि 200 प्रतिशत — शुल्क की शक्ति देता है (कथन 2 गलत)। पीयूष गोयल ने ISID सम्मेलन में किसानों के संवेदनशील हितों की रक्षा का दावा किया (कथन 3 सही)।

स्रोत

1. इंडियन एक्सप्रेस: "'Strong comparative advantage' for India after US trade deal: Piyush Goyal" (29 अक्टूबर 2026)। ISID सम्मेलन के उद्धरण; ग्राहम विधेयक का विराम; धारा 301 और G20 बयान।
2. न्यू इंडियन एक्सप्रेस: "US trade deal to protect sensitive sectors, give India competitive edge: Goyal" (29 अक्टूबर 2026)

टिप्पणी: समझौते का औपचारिक विवरण अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है; यह लेख मंत्री और अमेरिकी विदेश मंत्री के सार्वजनिक कथनों तक सीमित है।

PCSMANTRA.COM